



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 495]
No. 495]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 1997/अग्रहायण 26, 1919
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1997/AGRAHAYANA 26, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1997

(आय-कर)

सा. का. नि. 705 (अ).—चूंकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपव्ययन की रोकथाम के लिए स्वीडन किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के अनुसार उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाइयों को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में से पश्चात्त्वर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने के तीस दिन के पश्चात् अर्थात् दिसम्बर, 1997 के पच्चीसवें दिन को प्रवृत्त हो गया है ;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 7) की धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू होंगे ।

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे करधान
के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्वीडन किंगडम की सरकार

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडन किंगडम की सरकार,

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे करधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सौविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय उन करों पर लागू होगा जो एक सौविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए जाते हैं, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2. सकल आय, सकल पूंजी पर अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय तथा पूंजी पर लगने वाले करों के रूप में माने जायेंगे जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलक्ष्यों पर लगने वाले करों, उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों तथा मजदूरियों की सकल रकम पर लगने वाले कर तथा साथ ही साथ पूंजी वृद्धि पर लगने वाले करों की राशि भी शामिल है।

3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

§ क § भारत में :

§ i § आयकर और उस पर लगने वाला कोई अधिभार ; तथा

§ ii § पूंजी पर कर § घनकर § ;

§ जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा § ;

§ ख § स्वीडन में :

§ i § राष्ट्रीय आयकर § डेन स्टेटलिंग इनकोस्केटन § सहित आयकर जिसमें समुद्र पर कार्यरत कर्मचारियों पर कर सहित § सजोमेनस्केटन § और लाभान्शों पर रोके गए कर सहित § कूपेगस्केटन § ;

§ ii § अनिवासियों पर आयकर § डेन सरक्लि इनकोस्केटन फोर यूटेलेंड बोसट्ट § :

§ iii § अनिवासी कलाकारों और शिल्पादियों पर आयकर § डेन साररिक्लिइन-कोस्केटन फोर यूटेलेंड बोसट्ट आर्टिस्टर मुफला § ;

§ i/ § नगर आयकर § डेन कोम्युनाला इनकोम स्केटन § ;

§ 1/ § प्रसार प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत साधन पर कर § एक्सपेंशन मेडलस्केट § ;

§ 1/i § निवल घन कर :

§ जिसे इसके बाद "स्वीडिश कर" कहा जाएगा § ।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समरूप करों पर भी लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ § 3 § में उल्लिखित विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने क़राधान क़ानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक :
- §क§ "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र तथा इसमें उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर की वायु-सीमा-सम्मिलित है तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रमुखता सम्पन्न अधिकार अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;
- §ख§ "स्वीडन" पद से अभिप्रेत है स्वीडन किंगडम और भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होने पर इसमें राष्ट्रीय क्षेत्र, स्वीडन का राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार स्वीडन प्रमुखता सम्पन्न अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है ;
- §ग§ "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा स्वीडन अभिप्रेत है ;
- §घ§ "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त करायान कानूनों के तहत कर-योग्य इकाई के रूप में माना जाता हो ;
- §ङ.१§ "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए किसी निगमित निकाय के रूप में माना जाता हो ;
- §च§ "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
- §छ§ "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है जो किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

"राष्ट्रीय" पद से अभिप्रेत है :

§ i§ किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रकृता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;

§ ii§ कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो;

§ स§ "सक्षम अधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

§ i§ भारत में : केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय § राजस्व विभाग§ अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

§ ii§ स्वीडन में : वित्त मंत्री, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा अधिकारी जिसे इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ सक्षम अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो;

§ ज§ "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

§ i§ भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया हो ;

§ ii§ स्वीडन के मामले में "बेस्केटनिमिसर" जैसा कि कोम्मुनल स्काटलेजन, 1928 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया हो ;

§ ट§ "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार भारतीय कर अथवा स्वीडिश कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के बारे में देय हो जिस पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्थ-वण्ड का घटक हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू करने का प्रश्न है, उसमें अपेक्षित किसी ऐसे पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो अर्थ उन करों के संबंध में उस राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें उक्त अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता हो और उसमें वह

राज्य, उसका कोई राजनैतिक उपभाग, कोई स्थानीय अधिकार और उसका कोई सरकारी निकाय अथवा फौज भी सम्मिलित हो। किसी भागीदारी अथवा सम्पदा के संबंध में यह शब्द केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक ऐसी भागीदारी अथवा सम्पदा द्वारा प्राप्त की गई आय पर एक निवासी आय के रूप में उस राज्य में कर लगाया जाता हो। चाहे वह राशि स्वयं उसको प्राप्त होती हो अथवा उसके लाभभोगियों अथवा भागीदारियों द्वारा प्राप्त की जाती हो। "एक संविदाकारी राज्य के निवासी" पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से अथवा उसमें स्थित पूँजी से प्राप्त आय के बारे में छी कर लगाया जा सकता है।

2. जहाँ पैराग्राफ § 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

§ क § उसे उस संविदाकारी राज्य का ही निवासी माना जाएगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवासगृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं § महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र § ;

§ ख § यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसके दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह केवल उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आमतौर पर रहता हो;

§ ग § यदि वह आमतौर पर दोनों ही संविदाकारी राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी संविदाकारी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

§ घ § यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी परस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ पैराग्राफ § 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी संबंध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का, जिसमें उसका प्रभावी संबंध स्थान स्थित हो, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी परस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

अनुच्छेद - 5**स्थायी संस्थापन**

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः किया जाता है ।
2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :
 - § क § प्रबंध का कोई स्थान ;
 - § स § कोई शाखा ;
 - § ग § कोई कार्यालय ;
 - § घ § कोई कारखाना ;
 - § ङ § कोई कार्यशाला ;
 - § च § कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
 - § छ § कोई बिक्री बाजार ;
 - § ज § किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधा मुहैया करता हो ; और
 - § झ § कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ।
3. कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण, संयोजन अथवा प्रतिष्ठापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलापों को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छः महीने से अधिक की अवधि तक चलते रहते हों ।
4. किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का स्थायी संस्थापन होना और उस स्थायी संस्थापन द्वारा कारोबार किया जाना तभी माना जाएगा यदि वह उससे संबंधित सेवाएं अथवा सुविधाएं मुहैया कराता है अथवा उस राज्य में खनिज तेलों के पूर्वक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के लिए अथवा उनमें प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी किराए पर देता है ।
5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- ॥क॥ किसी उद्यम के माल अथवा फण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा माल की सुपूर्दगी ही के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- ॥ख॥ केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा सुपूर्दगी के प्रयोजनार्थ ही किसी उद्यम के माल अथवा फण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;
- ॥ग॥ किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ ही उक्त उद्यम के माल अथवा फण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;
- ॥घ॥ किसी उद्यम के लिए माल अथवा फण्य-वस्तुओं का केवल क़य करने अथवा सूचना पत्र करने के प्रयोजनार्थ ही कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- ॥ङ॥ उद्यम के लिए केवल किसी अन्य उपक्रममात्मक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- ॥च॥ उप-पैराग्राफ ॥क॥ से ॥ङ॥ में उल्लिखित कार्यकलापों के संयोजन के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, बशर्ते कि उस संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समस्त कार्यकलाप उपक्रममात्मक अथवा सहायक स्वरूप के हों ।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी प्जेंट के अलावा कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ ॥४॥ लागू होता है दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है वहां उस उद्यम के लिए उस व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्यकलाप के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति :

- ॥क॥ उस राज्य में उक्त उद्यम के नाम से संविदाएं करने का प्राधिकार रखता हो और वह उस प्राधिकार का आदतन प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैराग्राफ ॥५॥ में उल्लिखित कार्यकलापों तक ही सीमित न हों जिनका यदि किसी निश्चित कारोबारी स्थान से प्रयोग किया जाए तो उस बात से ही उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन उसे एक स्थायी संस्थापन नहीं बना देगा ।

- ॥ख॥ उसे ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा फण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता है जिसमें से वह उक्त उद्यम की ओर

से माल अथवा फण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता है ।

§ 8 § स्वयं उक्त उद्यम के लिए अथवा उक्त उद्यम के लिए और अन्य ऐसे उद्यमों के लिए पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः प्रथमोल्लिखित राज्य में आदेश प्राप्त करता है जो उस उद्यम की तरह नियंत्रण करते हों अथवा उसी तरह से नियंत्रित किए जाते हों और उसी तरह के नियंत्रण के अधीन हों ।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम पुनः बीमा के मामले को छोड़कर किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि यह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम फकत्र करता है अथवा स्वतंत्र हैसियत के पर्जेंट से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोशिम का बीमा करता है जिस पर पैराग्राफ § 8 लागू होता है ।

8. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन पर्जेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य पर्जेंट के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि जब ऐसे किसी पर्जेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का पर्जेंट नहीं समझा जाएगा ।

9. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो दूसरे राज्य में § चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा § कारोबार करती है, तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी एक कम्पनी को स्वतः ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति § कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित § से प्राप्त आय पर भी दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उक्त संविदाकारी राज्य के उस कानून के अंतर्गत है जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे

अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वाणिज्य में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, भवन, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोतों और अन्य प्रकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नावें और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उत्पन्न होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लाभों पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और निरन्तर उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन रहते हुए किए गए हों ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा फण्य-वस्तुएं सरीदी हैं ।
5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।
6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा विमानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे ।
2. कोई ऐसा परिवहन उद्यम जो कि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल या फण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त आधानों § जिसमें आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर भी शामिल हैं § के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा किराए से प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा जब तक कि ऐसे आधानों का केवल अन्य संविदाकारी राज्य में प्रयोग नहीं किया जाता ।
3. स्वीडन, डेनमार्क और नार्वे को वायु परिवहन कन्सोर्टियम, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम § प्स0 प0प्स0 § द्वारा प्राप्त लाभों के संबंध में पैराग्राफ § 1 § के उपबंध, लाभों के केवल ऐसे भाग पर ही लागू होंगे जो प्स0 प0 प्स0 स्वीडन 70 बी0 स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम § प्स0प0प्स0 § की स्वीडिश भागीदार द्वारा उस सहायता संघ § कन्सोर्टियम § में धारित भागीदारी के अनुरूप होगा ।
4. पैराग्राफ 1 के उपबंध, किसी फ्लू, संयुक्त व्यवसाय अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एनेन्सी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

जहां

§ क § एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

§ ख § वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ; और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रसी अथवा लगायी जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रसी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

दोहरे कराधान का कोई ऐसा मामला जो इस अनुच्छेद के लागू होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, उसको परस्परिक करार प्रक्रिया के तहत हल किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 10

लभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे लभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लभांश का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लभांशों की सकल राशि के 10% से अधिक नहीं होगा ।

यह पैराग्राफ उन लभांशों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लभांशों में से लभांश अदा किये जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लभांशों" शब्द का अभिप्राय, शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारी के अंश यावे न हों और इसमें निगमित अधिकारों से प्राप्त आय भी शामिल है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है ।

पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लब्धांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लब्धांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लब्धांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 जैसा भी मामला हो लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लब्धांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लब्धांश दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लब्धांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कम्पनी के अक्षिरित लब्धों पर अक्षिरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लब्धांश अथवा अक्षिरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह अर्जित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रसारित कर, व्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज को उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्रदान होगी बशर्ते कि यह निम्नलिखित के हितभागी स्वामित्व में हो अथवा उनके द्वारा दिए गए अथवा समर्थित ऋण अथवा उधार के संबंध में प्राप्त किया जाता हो :

§ i§ दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग, कोई सौविधिक निकाय अथवा कोई स्थानीय प्रधिकरण ; अथवा

§ ii§ भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत का निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत का लघु उद्योग विकास बैंक तथा भारत का औद्योगिक ऋण और निवेश निगम §आई.सी.आई.सी.आई. § ; और

स्वीडन के मामले में स्वीडन का अन्तरराष्ट्रीय विकास प्रधिकरण §एस.आई.डी.ए. § स्वीडकार्य §इन्टरनेशनल नेटिंगस्वीस्वीस्टेन्ड के लिए स्टरीलेसन§, स्वीड फंड इन्टरनेशनल ए. बी. अथवा स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट्स गारन्टी बोर्ड §एक्सपोर्ट क्रेडिट नामडेन§ ; अथवा

§ iii§ कोई अन्य संस्था जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दायों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के लक्ष्यों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध पत्रों अथवा ऋण पत्रों, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध पत्रों अथवा ऋण पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रिमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय । विलम्बित अदायगी के लिए अर्धदंड संबंधी प्रमारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नस्ते, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज अर्जित हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण दावे के बारे में व्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी हो । किन्तु जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन

अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गयी है और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब वह व्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, व्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गयी व्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संबिदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. किसी संबिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. पैराग्राफ § 1 के उपबंधों के होते हुए, ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संबिदाकारी राज्य में भी और उसके कानूनों के अनुसार कर लगेगा जिसमें वे उद्भूत हुई हों, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. § 1 इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए जिसमें चलचित्र प्रोपि फिल्मों, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है ।

§ ३। "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्श-दात्री सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में अदा की गयी कोई अदायगी अभिप्रेत है परन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गयी अदायगियां शामिल नहीं होंगी ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार या सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदा करने वाला उस राज्य का कोई निवासी हो तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो और ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की गई हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम जो सूचना के अधिकार या प्रयोग के लिए अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, अदा की गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदा की गई रकम से अधिक रकम पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को सद्यक रूप से ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13**पूंजीगत अभिलम्भ**

1. एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलम्भों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुए अभिलम्भों पर, जो एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का भाग है तथा दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सौविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन § अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ § अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलम्भ भी शामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्राप्त अभिलम्भों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

स्वीडिश, डेनिश तथा नार्वे की वायु परिवहन कन्सोर्टियम, स्कैन्डिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम § एस ए एस § को प्राप्त हुए अभिलम्भों के संबंध में, इस पैराग्राफ के उपबंध अभिलम्भों के केवल उत्तरे भागों पर लागू होंगे जिनमें उस कन्सोर्टियम में एस ए एस स्वीडिश ए.बी., स्कैन्डिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम § एस ए एस § की भागीदारी हो ।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर, जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी सौविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल हो, के संबंध में, उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न, किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर केवल उसी सौविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है बशर्ते कि उस निवासी पर वहां कर लगाया जाता हो । यदि उस निवासी पर वहां कर नहीं लगाया जाता हो, तब ऐसे अभिलम्भों पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

6. पैराग्राफ § 5 के उपबंधों के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति, जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी रहा है और जो दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी बन गया है, को किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलक्षणों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जाएगा यदि सम्पत्ति का अंतरण उस तारीख से अगले चार वर्षों के दौरान होता है जिस तारीख से वह प्रथमोल्लिखित राज्य का निवासी नहीं रहता है।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों से प्राप्त आय पर निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जबकि ऐसी आय पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा :

§ क § यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सौविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकता है जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

§ ख § यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबद्ध "वित्तीय वर्ष" में शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त हुई हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, सार्वजनिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 15

पराक्लृप्त वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन, किसी सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है, जब तक कि नियोजन दूसरे सौविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन इस प्रकार किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोत्तीखत राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

§ क § प्राप्तकर्ता संबंधित "वित्तीय वर्ष" में शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहता है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है ; और

§ ख § पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

§ ग § पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जा रहे जलयानों अथवा वायुयानों पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है। जहां स्वीडन के निवासी को स्वीडन डेन्मार्क और नार्वे के वायु परिवहन कन्सोर्टियम स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किसी विमान पर किए गए नियोजन से पारिश्रमिक प्राप्त होता है वहां ऐसे पारिश्रमिक पर केवल स्वीडन में ही कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी प्रकार की अन्य अदायगियां जो किसी सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा कलाकार के रूप में जैसे कि कोई थियेटर, चलांचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी कलाकार अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं कलाकार या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें कलाकार अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ § 1 और § 2 के उपबंध कलाकार अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए उसकी दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्रधिकरण की लोक नियुक्तियों द्वारा पूर्णतया सहायता की जाती हो । ऐसे मामले में, आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका कलाकार अथवा खिलाड़ी एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन, सामाजिक सुरक्षा अदायगियां और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत पिछले नियोजन, वार्षिकी और अदायगियों के संबंध में पेंशन और इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "वार्षिकी" पद से जीवन काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित अवधि के दौरान धनराशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने की बाध्यता के अंतर्गत आर्थिक रूप में निश्चित समय पर देय निश्चित राशि अभिप्रेत है ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. §क§ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से भिन्न, परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

§ख§ तथापि, ऐसे परिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यष्टि उस राज्य का निवासी है, जो :

§i§ उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा

§ii§ मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. §क§ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

§ख§ तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तभी लग सकेगा यदि व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है तो उसे प्रथमोल्लिखित राज्य की सरकार अथवा किसी अन्य संगठन अथवा संस्था द्वारा दिए जा रहे अधिमन्य परिस्थितियों पर ऋण और कर से छूट प्राप्त अनुदानों और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त प्रथमोल्लिखित राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

§ क § प्रथमोल्लिखित राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां ; और

§ ख § प्रथमोल्लिखित राज्य में नियोजन से प्राप्त परिश्रमिक जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 § दस हजार § स्वीडिश क्रेनर अथवा इसके समतुल्य राशि, जैसा भी मामला हो, से अधिक न हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया जाता हो और वह छः महीने अथवा उससे अधिक के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में रहा हो ।

2 • इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए बढ़ाए जाएंगे जो कि शुरू की गई शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस प्रथमोल्लिखित राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लेकर लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 21

प्रोफेसर, अध्यापक और शोध अध्येता

1 • कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोध अध्येता जो किसी संविदाकारी राज्य का, उस राज्य अथवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा उस राज्य की ऐसी किसी अन्य संस्था की ओर से निमंत्रण मिलने पर ऐसी संस्था में शिक्षण, व्याख्यान देने अथवा शोध कार्य करने मात्र के प्रयोजनार्थ तीन वर्षों से अनधिक के लिए दौरा करता है और जो उस दौरे के तत्काल पूर्व किसी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो उसे प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि प्रश्नगत संस्था उस संविदाकारी राज्य के सक्षम अधिकारी से उसके आगमन की तारीख से लेकर पहले वर्ष की अवधि के दौरान उसकी ऐसी गतिविधियों हेतु उसके परिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त करने की अनुमति ले लेता है और परवर्ती वर्षों में यह छूट केवल उसके द्वारा उस राज्य से बाहर किए गए कार्य से उद्भूत परिश्रमिक के संबंध में होगी ।

2 • यह अनुच्छेद ऐसे शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ हेतु किया गया हो ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ § 1१ के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ § 2१ में यथापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ § 1१ के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से लाटिरियों, वर्ग-पहेलियों, पुडूदौड़, कार्ड गेम और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों सहित रेसों अथवा जुएबाजी अथवा किसी भी प्रकार का स्वरूप की शर्त लगाने से आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 23

पूंजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

2. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति के अंश के रूप में चल सम्पत्ति द्वारा अथवा किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध नियत स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

3. किसी सौविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों और वायुयानों द्वारा और ऐसे जलयानों और वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी केवल उसी राज्य में कराधेय होगी ।

स्वीडन, डेनमार्क और नार्वे के वायु परिवहन कन्सोर्टियम स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम § प्स.प.प्स. § के स्वामित्व वाली पूंजी के संबंध में इस अनुच्छेद के उपबंध पूंजी के केवल ऐसे भाग पर ही लागू होंगे जो प्स. प. प्स. के स्वीडिश भागीदार, प्स.प.प्स. स्वीरज ए. बी. द्वारा धारित सहभागिता से संबंधित हो ।

अनुच्छेद - 24

दोहरे कराधान का अपकरण

1. दोनों सौविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित सौविदाकारी राज्यों में आय के कराधान मामलों को अधिशसित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जहां इस अभिसमय में उनके प्रतिकूल प्रवधान किए जाते हैं ।

2. भारत के मामले में, दोहरे कराधान का निम्नानुसार परिहार किया जाएगा :

§ क § जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार स्वीडन में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर स्वीडन में अदा की गई आयकर के बराबर की राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा चाहे वह प्रत्यक्षतः दी जाए अथवा स्रोत पर कटौती के द्वारा । तथापि ऐसी राशि आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कटौती दिए जाने से पूर्व संगणित की जाती है और जो उस आय से उद्भूत होती है जिस पर स्वीडन में कर लगेगा ।

§ ख § जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार स्वीडन में ही कर लगाया जा सकता है वहां भारत, भारतीय कर की क्रमिक दर का निर्धारण करते समय उस आय को हिसाब में लेगा जो केवल स्वीडन में कराधेय होगी ।

§ ग § जहां भारत का कोई निवासी ऐसी परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व रखता है जिन पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार स्वीडन में कर लगाया जा सकता है वहां भारत ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में स्वीडन में निवल सम्पत्ति पर अदा किए गए कर के

बराबर की राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती निवल सम्पत्ति पर भारतीय कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कटौती दिए जाने से पूर्व संगणित की जाती है और जो उन परिसम्पत्तियों के उपयुक्त है जिन पर स्वीडन में कर लगाया जा सकेगा।

3. स्वीडन के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :

§क§ जहां स्वीडन का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर भारत के कानून के तहत और इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहां स्वीडन ऐसी आय के संबंध में अदा किए गए भारतीय कर के बराबर की राशि पर विदेशी कर हेतु क्रेडिट के संबंध में स्वीडन के कानूनों के अधीन §जिसे यहां सामान्य सिद्धान्त में परिवर्तन किए बिना समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है§ ऐसी आय पर कर से कटौती की अनुमति देगा।

§स§ जहां स्वीडन का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार केवल भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां स्वीडन, स्वीडिश कर की क्रमिक दर का निर्धारण करते समय उस आय को हिसाब में लेगा जो केवल भारत में कराधेय होगी।

§ग§ इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ §क§ के उपबंधों के होते हुए भी, भारत की निवासी किसी कम्पनी द्वारा स्वीडन की निवासी किसी कम्पनी को अदा किए गए लाभों पर विदेश में सहायक कम्पनियों द्वारा स्वीडिश कम्पनियों को अदा किए गए लाभों पर कर से छूट को विनियमित करने वाले स्वीडिश कानून के उपबंधों के अनुसार स्वीडिश कर से छूट दी जाएगी।

§घ§ इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ §क§ के प्रयोजनार्थ अदा किए गए भारतीय कर पद में वह भारतीय कर शामिल हुआ माना जाएगा जिसे अदा कर दिया गया होता किन्तु जिसे भारतीय कानून में अंतर्विष्ट प्रोत्साहन उपबंधों के अंतर्गत प्रदान की गई किसी कर की ऐसी छूट अथवा कटौती के दिए जाने पर नहीं अदा किया गया जिसका उद्देश्य उस सीमा तक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता कि ऐसी छूट अथवा कटौती औद्योगिक अथवा विनिर्माण कार्यकलापों अथवा कृषि, मत्स्य ग्रहण अथवा पर्यटन §जिसमें रेस्तराँ और होटल भी शामिल हैं§ से प्राप्त लाभों के लिए दी जाती है बशर्ते कि ये कार्यकलाप भारत में ही निष्पादित किए गए हों। इस पैराग्राफ के उप-

पैराग्राफ § ग § के प्रयोजनार्थ स्वीडन के कर आधार पर संगणित 15% का कर पिछले वाक्य में उल्लिखित उन परिस्थितियों में ऐसे कार्यकलापों के लिए अदा कर दिया होना मान लिया जाएगा ।

सक्षम अधिकारी इस उपबंध को अन्य कार्यकलापों पर भी लागू करने पर सहमत हो सकते हैं ।

§ ड - § पैराग्राफ § य § के उपबंध केवल पहले दस वर्षों, जिस दौरान यह अभिसमय प्रभावी रहता है, के लिए लागू होंगे । इस अवधि को सक्षम अधिकारियों के बीच पारस्परिक समझौते के द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ।

§ ब § जहाँ स्वीडन का कोई निवासी ऐसी परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व रखता है जिन पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहाँ स्वीडन ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में भारत में अदा किए गए निवल सम्पत्ति पर अदा किए गए कर के बराबर की राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा । तथापि, ऐसी कटौती निवल सम्पत्ति पर स्वीडिश कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कटौती दिए जाने से पूर्व संगणित की जाती है और जो उन परिसम्पत्तियों के उपयुक्त है जिन पर भारत में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 25

सम-व्यवहार

1. एक संधिदाकारी राज्य के राष्ट्रकों पर दूसरे संधिदाकारी राज्य में ऐसे किसी करधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षा को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जा रहे अथवा लगाए जा सकने वाले करधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी एक अथवा दोनों संधिदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संधिदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संधिदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा करधान नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले करधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि एक संधिदाकारी राज्य दूसरे संधिदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण करधान के प्रयोजन हेतु कोई वैयक्तिक भत्ते, राहत अथवा कटौती प्रदान को बाध्य है, जो कि वह अपने निवासियों को प्रदान करता है । इससे

आगे, इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से रोकना है जो उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य को ऐसी ही किसी कंपनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इसका अर्थ यह है कि यह इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हो।

3. ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ § 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ § 6 के उपबंध लागू होते हैं, वहाँ एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रवृत्त व्याज, रायल्टियों और अन्य संवितरणों को ऐसे उद्यमों के कर योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही शर्तों के अधीन कटेती योग्य माना जाएगा मानो कि उन्हें प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था। इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया कोई स्वयं ऐसे उद्यम की कर योग्य पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही शर्तों के अधीन कटेती योग्य माना जाएगा मानो कि उन्हें प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई करायान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस करायान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लागू हो अथवा लागू हो सकती हो।

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपबंध प्रत्येक किस्म और विवरण के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 26

पारस्परिक करार विधि

1. जहाँ कोई व्यक्ति यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के देशीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों का ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है निम्न कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के तहत आता है

तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस पर कर लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम अधिकारी को आपत्ति उचित लगे और वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम अधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के देशीय कानूनों में कोई समय सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय के अर्थ निरूपण में अथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई या शंका उत्पन्न होती है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त लगे तो विचारों का आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से हो सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी ऐसी सूचना {दस्तावेजों सहित} का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन कर्तव्यों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय, विशेष रूप से ऐसे कर्तव्यों की घोषाघड़ी अथवा अपवर्चन को रोकने के प्रतिकूल नहीं हो, सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों

अथवा प्राधिकारियों {जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं} को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके बारे में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपिलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हों, जो अभिसमय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- §क§ उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपय करना ;
- §ख§ ऐसी सूचना मुहैया कराना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- §ग§ ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो §आर्डर पब्लिक§।

अनुच्छेद - 28

वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य एक दूसरे को इस अभिसमय से संबंधित करों की वसूली के साथ-साथ ऐसे करों से संबंधित व्यय, लागतों और सिविल वंड की वसूली में सहायता का वचन देते हैं जिन्हें इस अनुच्छेद में "राजस्व दावा" कहा गया है।

2. किसी राजस्व दावे की वसूली में किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन शामिल होगा कि उस राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दावे को अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ राजस्व दावा तभी अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को राजस्व दावा वसूल करने के लिए अपने आंतरिक कानून के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हो और करदाता को वसूली रोकने का और कोई अधिकार न प्राप्त हो।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी। तथापि, प्रथमोल्लिखित

राज्य को उन सर्चों की प्रतिपूर्ति का ठेक होगा, यदि कोई हो, जो ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान किए गए हों और यह प्रतिपूर्ति उस सीमा तक की जाएगी जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों के बीच में परस्परिक सहमति हो गई हो ।

4. इस अनुच्छेद की किसी भी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य पर यह बाध्यता लागू की जाए कि वह उन प्रशासनिक उपकरणों से भिन्न तरह के उपकरणों को जो उसको स्वयं के करों की वसूली में किए जाते हैं अथवा वह ऐसे प्रशासनिक उपकरणों को कि उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हों ।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशनों और कौंसली पदों के सदस्य

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशनों और कौंसली पदों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 30

प्रकृत होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा किए जाने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह अभिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति के तीस दिन बाद प्रभावी हो जाएगा ।

3. इस अभिसमय के उपबंध निम्न प्रकार से प्रभावी होंगे :

§ क § भारत में :

§ i § जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ;

§ ii § जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ;

§ स § स्वीडन में :

§ i § जिस वर्ष में अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद उद्भूत आय पर करों के संबंध में ;

§ ii § जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय लागू होता है उसके अनुवर्ती दूसरे कैलेंडर वर्ष को अथवा उसके बाद जिस कर का निर्धारण किया जाता है उसके लिए निवल धनकर के संबंध में ।

4. इस अभिसमय और संलग्न प्रोटोकोल के प्रवृत्त होने पर प्रोटोकोल संहिता आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडन किंगडम की सरकार के बीच 7 जून, 1988 का अभिसमय समाप्त हो जाएगा प्रोटोकोल संहिता उक्त 1988 अभिसमय के उपबंध उस तारीख से निष्प्रभावी हो जाएंगे जिस तारीख से इस अभिसमय और इसके साथ के प्रोटोकोल के तदनुसंगी उपबंध पहली बार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार प्रभावी होंगे ।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह अभिसमय उस समय तक लागू रहेगा जब तक किसी संधिदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संधिदाकारी राज्य किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का लिखित नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी परिस्थिति में अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

§ क § भारत में :

§ i § जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

§ ii § जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

§ स § स्वीडन में :

§ i § छह महीने की अवधि की समाप्ति पर अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को या उसके बाद उद्भूत आय पर करों के संबंध में ;

§ iii छह महीने की अवधि की समाप्ति पर दूसरे अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में अथवा उसके बाद निर्धारित कर के लिए निम्न घनकर पर कर के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिक रूप से प्रधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तानवे के जून माह के चौबीसवें दिन, हिन्दी, स्वीडिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निम्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । किसी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(सतपाल महाराज)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

स्वीडन किंगडम की
सरकार की ओर से
(थॉमस ऑस्ट्रॉस)
कराधान मंत्री

प्रेतोक्केल

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडन किंगडम की सरकार के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित, अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे :-

अनुच्छेद 2 के संदर्भ में :

स्वीडिश सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत अदा की गई फीस और विशेष केतन पर अधिनियम §1990:659 के अनुसार अर्जित आय पर कर तथा विशेष केतन पर अधिनियम §1991:689 के अनुसार पेंशन लागतों पर कर इस अभिसमय में शामिल नहीं हैं ।

अनुच्छेद 7 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में, जहां किसी एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से माल अथवा पम्प-वस्तुएं बेचता है अथवा कारोबार करता है तो उस स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण उद्यम द्वारा प्राप्त कुल धनराशि के आधार पर नहीं किया जाएगा परन्तु इसका निर्धारण केवल ऐसी बिक्री अथवा कारोबार के लिए स्थायी संस्थापन की वास्तविक गतिविधि से उद्भूत पारिश्रमिक के आधार पर किया जाएगा । विशेष रूप से सर्वेक्षण, आपूर्ति, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर अथवा परिसर निर्माण अथवा

संस्थापना अथवा सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए संधिदा के मामले में जब उद्यम को कोई स्थायी संस्थापन हो, तो ऐसे स्थायी संस्थापन के लक्षण संधिदा की कुल राशि के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे जो उस संधिदाकारी राज्य, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है, में प्रभावी दंग से किया जाता है।

अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 10 §लभांश§, 11 §व्याज§ और 12 §रायटियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस§ के संबंध में यदि भारत और किसी तीसरे राज्य, जो ओईसीडी का सदस्य हो, के बीच किसी अभिसमय, करार अथवा प्रोटोकोल के तहत भारत लभांश, व्याज, रायटियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत पर अपने करधान को ऐसी किसी दर तक सीमित करता है जो आय की उक्त आय मदों पर उस दर या परिधि की तुलना में कम हो अथवा जिसकी परिधि अधिक सीमित हो जिस दर या परिधि की इस अभिसमय में व्यवस्था की गई है तो आय की उक्त मदों पर उस अभिसमय, करार या प्रोटोकोल में व्यवस्थित वही दर अथवा परिधि इस अभिसमय के अंतर्गत भी लागू होगी।

अनुच्छेद 25 के संदर्भ में :

भारत में स्वीडिश कंपनियों के स्थायी संस्थापनों का करधान किसी भी हालत में उनसे मिलती-जुलती भारतीय कंपनियों के उस करधान से अधिक भिन्न नहीं होगा जिसका इस अभिसमय पर हस्ताक्षर की तारीख को भारतीय कानून में प्रवधान किया गया है।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तानवे के जून माह के चौबीसवें दिन, हिन्दी, स्वीडिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(सतपाल महाराज)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

स्वीडन किंगडम की
सरकार की ओर से
(थॉमस ऑस्ट्रॉस)
करधान मंत्री

[अधिसूचना सं. 10475/फा. सं. 505/2/81-वि.क.प्र.]

के. डी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

3197 GE/92-5

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 1997

(INCOME-TAX)

G.S.R. 705(E).--WHEREAS the annexed Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital shall come into force, on the twenty-fifth day of the December, 1997, thirty days after the receipt of the latter of the notifications by both the Contracting States to each other of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with Article 30 of the said Convention;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred under section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital and with a view to promoting economic cooperation between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

(3) The existing taxes to which this Convention shall apply are in particular:

(a) In India:

(i) the income tax, including any surcharge thereon; and

(ii) the tax on capital (the wealth tax);
(hereinafter referred to as "Indian tax");

(b) in Sweden:

(i) the income tax, including the national income tax (den statliga inkomstskatten), including the tax on employees at sea (sjömansskatten) and the withholding tax on dividends (kupongskatten);

(ii) the income tax on non-residents (den

sarskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

(v) the tax on means intended for expansion purposes (expansionsmedelsskatt); and

(vi) the net wealth tax;
(hereinafter referred to as "Swedish tax").

(4) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph (3). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
- (b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other

maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Sweden, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means:
 - (i) in India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised

representative;

(ii) in Sweden: the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

(j) the term "fiscal year" means:

(i) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;

(ii) in the case of Sweden "beskattningsår" as defined under Section 3 of the Kommunkattlagen, 1928;

(k) the term "tax" means Indian tax or Swedish tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State, a political subdivision, a local authority and any governmental body or agency thereof. In the case of a partnership or estate the term applies only to the extent that the income derived by such partnership

or estate is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

The term "resident of a Contracting State" does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1), a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a sales outlet;
- (h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and
- (i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

(3) A building site or a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activities continue for a period of more than six months.

(4) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

(5) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph (8) applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (5) which, if exercised through a

fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.

(7) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (8) applies.

(8) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

(9) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

(2) Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

(3) With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that

enterprise and taxed accordingly.

Any case resulting in double taxation from the application of this Article may be resolved under the mutual agreement procedure.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may

be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State provided it is derived and beneficially owned by, or derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by:

(i) the Government, a political subdivision, a statutory body, or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Export-Import Bank of India, the

National Housing Bank, the Small Industries Development Bank of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI); and

in the case of Sweden, the, Swedish International Development Authority (SIDA), SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd), Swedfund International AB or The Swedish Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden); or

(iii) any other institution as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then

such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties and fees for technical services

(1) Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

(3) (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) The term "fees for technical services" means

payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws

of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Gains from alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

(5) Gains from the alienation of any property other

than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident, provided that such resident is subject to tax thereon in that State. If the resident is not subject to tax thereon, then such gains may be taxed in the other Contracting State.

(6) Notwithstanding the provisions of paragraph (5), gains from the alienation of any property derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the property occurs at any time during the four years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in the other State; or
- (b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the

independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS).

such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportspersons

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an artiste, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an artiste or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the artiste or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the artiste or sportsperson are exercised.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2), shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by artistes or sportspersons if the visit to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or of a political subdivision or local authority thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the artiste or sportsperson is a resident.

Article 18

Pensions, social security payments and annuities

(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment, annuities and payments under the Social Security legislation arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

(2) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

Government service

- (1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- (2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to

that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students and apprentices

(1) A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training shall, besides loans on preferential conditions provided by the Government or any other organisation or institution of the first-mentioned State and tax exempt grants and scholarships, be exempt from tax in the first-mentioned State on:

- (a) payments made to him by persons residing outside the first-mentioned State for the purpose of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in the first-mentioned State, in an amount not exceeding 10,000 (ten thousand) Swedish Kronor or its equivalent amount during any fiscal year, as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance and that his stay in the first-mentioned State lasts for six months or more.

(2) The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.

Article 21

Professors, teachers and research scholars

(1) A professor, teacher or research scholar who visits a Contracting State at the invitation of that State or of a university, college, school or other such institution of that State not exceeding three years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution and who is, or was immediately before that visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State, provided that the institution in question receives approval from the competent authority of that Contracting State, on his remuneration for such activity during the period of the first year from the date of his arrival and in the subsequent years the exemption will be only in respect of remuneration derived by him from outside that State.

(2) This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

Other income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient

of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23

Capital

(1) Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to capital owned by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of this Article shall apply only to such part of the capital as relates to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

Article 24

Elimination of double taxation

(1) The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

(2) In the case of India, double taxation shall be avoided as follows:

- (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Sweden whether directly or by way of deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden.
- (b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Sweden, India may, when determining the graduated rate of Indian tax, take into account the income which shall be taxable only in Sweden.
- (c) Where a resident of India owns assets which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, India shall allow as a deduction from tax on such

assets an amount equal to the tax on net wealth paid in Sweden in respect of such assets. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Indian tax on net wealth as computed before the deduction is given which is appropriate to the assets which may be taxed in Sweden.

(3) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

- (a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in India, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Indian tax paid in respect of such income.
- (b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in India, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in India.
- (c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.
- (d) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the term "Indian tax paid" shall be deemed to include the Indian tax which would have been paid but for any exemption or reduction of tax granted under

incentive provisions contained in the Indian law designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial or manufacturing activities or from agriculture, fishing or tourism (including restaurants and hotels) provided that the activities have been carried out within India. For the purpose of subparagraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be considered to have been paid for such activities under those conditions mentioned in the previous sentence.

The competent authorities may agree to extend the application of this provision also to other activities.

- (e) The provisions of paragraph (d) shall apply only for the first ten years during which this Convention is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.
- (f) Where a resident of Sweden owns assets which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Sweden shall allow as a deduction from tax on such assets an amount equal to the tax on net wealth paid in India in respect of such assets. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish tax on net wealth as computed before the deduction is given which is appropriate to the assets which may be taxed in India.

Article 25

Non-discrimination

- (1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and

connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs or reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. Further this provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.

(3) Except where the provisions of Article 9, paragraph (7) of Article 11, or paragraph (6) of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subject in the

first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

Collection assistance

(1) The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates, together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a "revenue claim".

(2) Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

(3) Amount collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

(4) Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

Article 29

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

Entry into force

(1) The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Convention.

(2) This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

(3) The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in India,

(i) in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force;

(ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which this Convention enters into force;

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes on income, on income derived on or after the first

day of January of the year next following that of the entry into force of the Convention;

- (ii) in respect of tax on net wealth, for tax which is assessed on or after the second calendar year following that in which the Convention enters into force.

(4) The Convention of 7 June 1988 between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital with Protocol shall terminate upon the coming into force of this Convention and accompanying Protocol. The provisions of the said 1988 Convention with Protocol shall cease to have effect from the date on which the corresponding provisions of this Convention and accompanying Protocol shall, for the first time, have effect according to the provisions of paragraph 2 of this Article.

Article 31

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Convention shall cease to have effect:

(a) in India,

- (i) in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of

3191/GI/97-10

April following the calendar year in which the notice of termination is given;

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes on income, on income derived on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period;

(ii) in respect of tax on net wealth, for tax which is assessed in or after the second calendar year following the end of the six months period.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Convention.

Done in duplicate at New Delhi, this 24th day of June, 1997, in the Swedish, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

For the Government of
the Republic of India

(SATPAL MAHARAJ)
Minister of State for Finance

For the Government of
the Kingdom of Sweden

(Thomas Ostros)
Minister of Taxation

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed that the following shall form an integral part of the Convention:

With reference to Article 2:

The fees paid under the Swedish Social Security Legislation and according to the provisions of the Act (1990:659) on Special salary tax on earned income and the Act (1991:687) on Special salary tax on pension costs are not included in this Convention.

With reference to Article 7:

In respect of paragraphs (1) and (2) of Article 7, where an enterprise of one of the Contracting States sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of the remuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business. Especially, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of such permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated.

With reference to Articles 10, 11 and 12:

In respect of Articles 10 (Dividends), 11 (Interest) and 12 (Royalties and fees for technical services), if under any Convention, Agreement or Protocol between India and a third State which is a

member of the OECD, India limits its taxation at source on dividends, interest, royalties or fees for technical services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, the same rate or scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply under this Convention.

With reference to Article 25:

The taxation in India of permanent establishments of Swedish companies, shall in no case differ more from the taxation of similar Indian companies than is provided by the Indian law on the date of signature of this Convention.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi, this 24th day of June, 1997, in the Swedish, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

For the Government of
the Republic of India

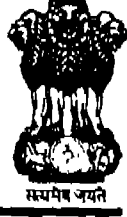
(SATPAL MAHARAJ)
Minister of State for Finance

For the Government of
the Kingdom of Sweden

(Thomas Ostros)
Minister of Taxation

[Notification No. 10475/F. No. 505/2/81-FTD]

K. D. GUPTA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

11/28
9/3/98

सं० 494]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 1997/अग्रहायण 25, 1919

No. 494]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 1997/AGRAHAYANA 25, 1919

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री (नाम परिवर्तन) संशोधित नियम, 1997 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 के नियम 3 के, उप नियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

“(ड) जहां यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर का समूह है और कोई ऐसा अधिकारी, जो समूह का प्रधान है गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व किसी कैडेट के नाम आरक्षण को अन्य कैडेट के नाम में परिवर्तन करने का लिखित में निवेदन करता है।

परन्तु परिवर्तन के लिए कोई ऐसा अनुरोध केवल एक बार मंजूर किया जाएगा।

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में समूह की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए उक्त अनुरोध मंजूर नहीं किया जाएगा।”

[सं. 97/टी.जी.-1/20/पी]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 16 अगस्त, 1990 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 708 (ई) के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 1997

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of the section 60 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (i) These rules may be called the Passengers-(Change of Names) Amendment Rules, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In rule 3 of the Passengers (Change of Names) Rules, 1990, in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

“(e) Where the passengers are a group of Cadets of National Cadet Corps and any officer who is the Head of the group makes a request in writing at least twenty four hours before the scheduled departure of the train that the reservation made in the name of any cadet be transferred to any other cadet;

Provided that any such request for change shall be granted only once;

Provided further that in no case such request for change in excess of ten per cent of the total strength of the group shall be granted”.

[No. 97/TG.1/20/P]

D. P. TRIPATHI, Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 708 (E) dated the 16th August, 1990.